भारतीय रिज़र्व बैंक की प्लैटिनम जुबली के भव्य समापन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन *

भारतीय रिज़र्व बैंक के प्लैटिनम जुबली समारोह के अवसर पर मुंबई में रहना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मेरे लिए तो यह आतुरता का भी एक विशेष क्षण है। मैंने इस संस्था के गवर्नर के रूप में कुछ बहुत ही स्मरणीय वर्ष व्यतीत किये हैं। उन स्मरणीय दिनों के दौरान हुई कई नई मित्रताओं की याद को मेरी पत्नी और मैं संजोए हुए हैं। हमारे देश के आर्थिक इतिहास में बहुत ही कठिन समय में जब मैं भारत का वित्त मंत्री था, उस समय आर्थिक सुधारों की कार्यसूची के कार्यान्वयन में भारत सरकार की सहायता करने में भारतीय रिज़र्व बैंक ने जो भूमिका अदा की थी, उसको मैं बड़े आभार के साथ याद करता हूं। इस महान संस्था की प्लैटिनम जुबली में प्रधानमंत्री के रूप में शामिल होना सच में मेरे लिए भावुकतापूर्ण अनुभव है।

जब वर्ष 1991 में मैंने वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभाली थी, उस समय मैं इस बात से सहमत था कि आर्थिक उदारीकरण और सुधार केवल तब ही सफल हो सकते हैं जब बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों में भी व्यापक सुधार किये जायें। मैंने अपने पुराने मित्र और भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर श्री एम. नरसिम्हम से इस महत्वपूर्ण विषय पर सिफारिश करने के लिए समिति की अध्यक्षता करने के लिए कहा। नरसिम्हम समिति की रिपोर्ट में सुधारों की व्यापक कार्यसूची को रेखांकित किया गया, जिसने आने वाले वर्षों में हमें क्या करने की जरूरत है, उसके खाके के रूप में कार्य किया।

यदि उन सुधारों को उस समय के गवर्नर श्री एस. वेंकिटरमन और बाद में डॉ. रंगराजन से उत्साहपूर्ण समर्थन न मिला होता, जैसाकि उनसे मिला, तो उनको लागू करना कठिन होता। श्री वेंकिटरमन के उत्तराधिकारी के रूप में डॉ. रंगराजन ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जिनमें विशेषकर सरकारी घाटे का स्वतः मौद्रिकरण समाप्त करना शामिल है, में वित्तीय सुधारों को आगे बढ़ाया।

भारत में सामान्यतः आर्थिक सुधारों के साथ वित्तीय क्षेत्र में सुधारों को धीरे-धीरे लागू किया गया। हमारे

* 1 अप्रैल 2010 को राष्ट्रीय नाट्य कला केंद्र, मुंबई में भारतीय रिज़र्व बैंक की प्लैटिनम जुबली के भव्य समापन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का संबोधन।

भारतीय रिज़र्व बैंक की प्लैटिनम जुबली का भव्य समापन समारोह

भारतीय रिज़र्व बैंक की प्लैटिनम जुबली के भव्य समापन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का संबोधन

वृद्धिशील दृष्टिकोण के बारे में अक्सर हमारी आलोचना की गई, जिसके बारे में आलोचक यह शिकायत करते थे कि गति बहुत धीमी है। लेकिन बहुत ही कम लोग इस बात से इनकार करेंगे कि इन वर्षों में हमने महान कार्य पूरा किया है और भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमने उद्योग और निवेश पर दम घोटू नियंत्रण को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। हमने अर्थव्यवस्था को विदेशी व्यापार के लिए खोल दिया है, प्रशुल्कों को घटा दिया है और बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दर को अपना लिया है। हमने पूंजी पर नियंत्रणों को उदार बनाया है जिससे अर्थव्यवस्था शेयर बाज़ार में एफडीआई और एफआईआई, दोनों के रूप में पूंजी के पर्याप्त अंतर्वाह को आत्मसात कर सकेगी। हाल के वर्षों में विदेशी निवेश भी दुतरफा प्रवाह वाला बन गया है क्योंकि अनेक भारतीय कंपनियों ने निवेश या अधिग्रहण के द्वारा विदेशों में अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी है।

यह सब बिना किसी गंभीर बृहत् आर्थिक संकट या विस्तारित अवधि में गंभीर मुद्रास्फीति का अनुभव किये प्राप्त किया गया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि वास्तविक अर्थव्यवस्था स्पष्ट रूप से फलीफूली है। गत दो दशकों में जीडीपी की विकास दर में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है, जो वैश्विक आर्थिक संकट से ठीक पहले के चार वर्षों की अवधि में प्रति वर्ष 9% की अभूतपूर्व वृद्धि के चरम बिन्दु पर पहुंच गई थी। गरीबी भी धीरे-धीरे कम हो रही है, हालांकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

इस रूपांतरण में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रमुख भूमिका अदा की है। यह बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधारों में अग्रणी संस्था रहा है तथा बढ़ते खुले एवं उदारीकृत आर्थिक वातावरण में बृहत् आर्थिक प्रबंध के जटिल कार्य से संबद्ध कई अन्य मुद्दों पर सरकार के विश्वस्त सलाहकार के रूप में कार्य किया है। असल में, यह हमारी विशाल संस्थाओं में से एक है जिन पर हम सच में गर्व कर सकते हैं।

गत दो वर्ष दुनिया भर की सरकारों और केंद्रीय बैंकों के लिए मुश्किल भरे वर्ष रहे हैं। अनिश्चित मूल्य के तथाकथित 'वित्तीय नवोन्मेष' से अत्यधिक ऋण विस्तार और आस्ति मूल्य मुद्रास्फीति, दोनों को बढ़ावा मिला तथा शिथिल विनियामक माहौल के कारण जोखिम का संचय हो गया, जिसको ठीक प्रकार से नहीं समझा गया और अंततः गंभीर संकट उत्पन्न हो गया।

भारत इन घटनाक्रमों से अपेक्षाकृत पृथक रहा, क्योंकि हमारी वित्तीय प्रणाली वैश्विक प्रणाली से काफी कम एकीकृत हुई थी। हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक संपत्ति के बुलबुल से उठे खतरे के बारे में दूरदर्शी होने के लिए श्रेय पाने का पात्र है। यहां मौजूद पूर्व गवर्नर श्री रेड्डी द्वारा संकट से पहले ही स्थावर संपदा के विरुद्ध बैंक ऋण कम करने की कार्रवाई के कारण इस क्षेत्र में बैंकों का ऋण निवेश कम रहा।

सितम्बर 2008 में जब संकट का विस्फोट हुआ, भारतीय रिज़र्व बैंक ने नई और बदली हुई परिस्थितियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण कम करने के अपने पूर्ववर्ती निर्णय को तत्काल उलट दिया। तेजी से श्रृंखलाबद्ध कदम उठाते हुए सीआरआर और रेपो एवं रिवर्स रेपो दरों को कम कर दिया। गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों की बैंक ऋण तक पहुंच बढ़ाने के लिए भी कुछ पहल की गईं। संकट के प्रारंभिक सप्ताहों में निजी क्षेत्र के कुछ बैंकों से संत्रस्त आहरण के कुछ संकेतों को सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक, दोनों द्वारा पुनः यह सुदृढ़ आश्वासन देकर रोका गया कि हमारे बैंक सुदृढ़ हैं और उनको पूरा समर्थन दिया जायेगा।

वित्तीय और आर्थिक प्रबंध के क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धि इस कठिन समय के दौरान भारतीय वित्तीय प्रणाली के स्थिर बने रहना सुनिश्चित करना रहा है। इस अवधि में गवर्नर श्री सुब्बाराव और भारतीय रिज़र्व बैंक में उसकी टीम को उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के लिए मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक की प्लैटिनम जुबली का भव्य समापन समारोह

भारतीय रिज़र्व बैंक की प्लैटिनम जुबली के भव्य समापन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का संबोधन

संकट अब लगभग समाप्त हो गया है, अतः आने वाले वर्षों में हमें जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उनको देखने की जरूरत है।

औद्योगीकृत देश लगभग निश्चित रूप से धीमी विकास की अवधि की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर भारत भविष्य में बेहतर कार्यनिष्पादन की अच्छी संभावनाओं के साथ अधिक मजबूत बन कर उभर रहा है। हमारे जीडीपी की तुलना में हमारी घरेलू बचत दर बढ़कर लगभग 35% हो गई है और हमारी घरेलू निवेश दरें लगभग 37% हो गई हैं। हमारे पास अत्यधिक उद्यमी निजी क्षेत्र है जिसने यह प्रदर्शित कर दिया है कि यह वैश्विक बाज़ारों में न केवल सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में बल्कि परंपरागत निर्माण के क्षेत्र में भी प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकता है। हमारे पास अच्छी गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त महत्वपूर्ण विशाल मानव संसाधन है जो आज की दुनिया में हमें निश्चित रूप से लाभ की स्थिति में रखता है। भौगोलिक रूप से हम ऐसे महाद्वीप में स्थित हैं जो आर्थिक महत्व प्राप्त कर रहा है और आने वाले वर्षों में विश्व अर्थव्यवस्था का प्रमुख संवाहक होने जैसे लगता है।

हमें इन क्षमताओं का दोहन करना है और विकास के उच्च पथ पर यथाशीघ्र लौटना है। मुझे विश्वास है कि हम 9% की विकास दर पर ग्यारहवीं योजना के समाप्त होने तक लौट जायेंगे और उसके बाद इससे भी बेहतर करेंगे। अतः मैंने योजना आयोग से कहा है कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 10% की समावेशी विकास दर प्राप्त करने के लिए व्यवहार्यता की तलाश करें।

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई नीतिगत परिवर्तन करने होंगे। मैं संक्षेप में उनके बारे में बताता हूं जो भारतीय रिज़र्व बैंक से संबंधित हैं।

जैसे जैसे हम तीव्र और समावेशी विकास को हासिल करने के अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ेंगे, वैसे-वैसे हमारी मौद्रिक और वित्तीय नीतियां तीन महत्वपूर्ण उद्देश्यों से निर्देशित होनी चाहिए। पहला, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखा जाता है, क्योंकि यह आम जनता को सबसे ज्यादा ठेस पहुंचाती है और आर्थिक संकेतों का मिथ्यावर्णन करती है। दूसरा, उन्हें बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि अन्यथा हम वित्तीय संकट का सामना करने का जोखिम उठाते हैं जिसकी वास्तविक अर्थव्यवस्था पर भी हमेशा उच्च लागत पड़ती है। तीसरा, उन्हें तीव्र और समावेशी विकास की वित्तीय मध्यवर्ती जरूरतों को पूरा करना चाहिए।

इन उद्देश्यों को मौद्रिक और वित्तीय नीतियां केवल तब ही कुशलतापूर्वक हासिल कर सकती हैं जब बृहत् आर्थिक वातावरण सुदृढ़ हो। इस संदर्भ में राजकोषीय घाटे का आकार एक प्रमुख मापदंड है। गत दो वर्षों में हमने राजकोषीय घाटे में अत्यधिक वृद्धि की अनुमति प्रदान की है क्योंकि हमने वैश्विक आर्थिक संकट का सामना किया है। इसके लिए मैं मेरे साथी और मित्र श्री प्रणब मुखर्जी की प्रशंसा करता हूं। इसे अब उलटना चाहिए। अतः हम अर्थव्यवस्था को राजकोषीय रूप से व्यवहार्य पथ पर पुनः लाने के लिए दृढ़ रूप से प्रतिबद्ध हैं। इसमें राजकोषीय घाटा वर्ष 2009-10 में जीडीपी के 6.8% से घटाकर वर्ष 2010-11 में 5.5% करना तथा अगले दो वर्षों में और घटाकर वर्ष 2012-13 में 4.1% तक पहुंचना शामिल है।

यदि राजकोषीय लक्ष्यों को हासिल कर लिया जाये, तो मौद्रिक नीति के लिए मुद्रास्फीति को नियंत्रण में करना बहुत आसान हो जायेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि राजकोषीय असंतुलन को दूर करने में मौद्रिक नीति कोई भूमिका अदा नहीं करती है। हालांकि, उस स्थिति में घाटे का समायोजन करने में मौद्रिक विस्तार से बचने की इसकी भूमिका अनिवार्यतः प्रतिरक्षात्मक होगी, क्योंकि ऐसा

भारतीय रिज़र्व बैंक की प्लैटिनम जुबली का भव्य समापन समारोह

भारतीय रिज़र्व बैंक की प्लैटिनम जुबली के भव्य समापन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का संबोधन

समायोजन ही मुद्रास्फीति को रोकेगा। समस्या यह है कि ऐसी स्थिति में मौद्रिक अनुशासन मुद्रास्फीति को रोकने में सहायता कर सकता है लेकिन यह निजी निवेश के लिए संसाधनों की उपलब्धता या दीर्घकालिक ब्याज दरों, दोनों विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, बड़े राजकोषीय घाटों के नकारात्मक प्रभाव को समायोजित नहीं करेंगे।

असल में पूंजी प्रवाह के लिए खुली अर्थव्यवस्था में राजकोषीय असंतुलनों के बावजूद मौद्रिक अनुशासन से ब्याज दरें बढ़ सकती हैं जो अत्यधिक पूंजी प्रवाह को प्रेरित कर सकती हैं जिनका विनिमय दर पर दबाव पड़ सकता है अधिक बृहत्-प्रबंधन का कार्य और उतना ही मुश्किल हो सकता है। यह असंभव त्रित्व की सुपरिचित समस्या है। पूंजी की गतिशीलता वाली अर्थव्यवस्था में आप विनिमय दर में स्थिरता और साथ ही स्वतंत्र मौद्रिक नीति नहीं रख सकते हैं। इस संतुलनकारी नाजुक कार्य को करने की जिम्मेदारी भारतीय रिज़र्व बैंक पर आती है। इसके कार्य को इस तथ्य ने आसान बना दिया है कि पूंजी खाता पूरी तरह से खुला नहीं है और ऋण, विशेषकर अल्पकालिक ऋण के अंतर्वाह पर प्रतिबंध हैं। पूंजी खाते को खोलने की गति के बारे में सावधानी हमारी नीति की सोची-समझी विशेषता है और दृष्टिकोण को जारी रखने के सही कारण हैं।

दूसरा उद्देश्य, जिसका मैंने जिक्र किया है, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने की जरूरत है। इस संबंध में हाल के संकट से सीखने के लिए महत्वपूर्ण सबक हैं। अत्यधिक जोखिम उठाने से बचने के लिए वित्तीय विनियमन तैयार किये जाने चाहिए और यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिये कि बैंकों को अपने तुलनपत्रों को चक्रीय परिवर्तनों से बचाना चाहिए। हमें विनियामक बचाव के रास्तों के बारे में विशेषरूप से चौकन्ना रहना चाहिए, जो प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं। सूक्ष्म विवेकपूर्ण विनियमन, जो अलग-अलग संस्थाओं की स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बृहत् विवेकपूर्ण प्रतिफलों के पूरक हो, जो संपूर्ण प्रणाली की स्थिरता से संबंधित होते हैं।

इन सभी मुद्दों की वित्तीय स्थिरता बोर्ड द्वारा जांच की जा रही है जो वित्तीय विनियमन की सम्मत संरचना तैयार करने के लिए एक बहुपक्षीय मंच है। जी-20 के संदस्य के रूप में अब हम इस बोर्ड के पूर्ण सदस्य हैं और उस निकाय में भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे अवरोधों और विशेष परिस्थितियों को प्रदर्शित करते हुए हमारी चिंताएं नई अंतर्राष्ट्रीय सर्वसम्मति में पूरी तरह से प्रदर्शित होती हैं जो वित्तीय स्थिरता बोर्ड के विचार-विमर्श से उभरती हैं।

तीसरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय प्रणाली तीव्र और समावेशी विकास की मध्यस्था अपेक्षा को पूरा करती है। यह हमारे सामने एक प्रकार का सर्वाधिक चुनौतिपूर्ण कार्य है। हमारी वित्तीय प्रणाली ने स्थिर होने का प्रमाण दे दिया है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इसमें और विकास तथा परिष्करण करने की जरूरत नहीं है। मैं कई बार ऐसा कहते हुए सुनता हूं कि हमारे पृथक्करण ने हमारी अच्छी सहायता की है, अतः हमें प्रयोग करने तथा इस क्षेत्र में और उदारीकरण करने से बचना चाहिए। मुझे लगता है कि संकट से सीखने का यह गलत सबक होगा। हमें इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि हमारी स्थिति में वित्तीय नवोन्मेष महत्वपूर्ण नहीं है।

हमारी बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली अर्थव्यवस्था के आकार की तुलना में अपेक्षाकृत छोटी है तथा ऐसे कई आयाम हैं जिनमें इसे विकास करना चाहिए ताकि यह आर्थिक विकास, जिसका हमने उद्देश्य बना रखा है, की उच्चतर दरों को पाने में सहायता कर सके। विकास की ये उच्चतर दरें ऐसे आर्थिक वातावरण में हासिल होंगी, जिनमें भारत विश्व के लिए खुला रहेगा और भारतीय कंपनियां दुनियाभर में परिचालित होंगी। भविष्य में विदेशी मुद्रा जोखिम का

प्रबंध धीरे-धीरे महत्वपूर्ण हो जायेगा और वित्तीय प्रणाली को हमारी कंपनियों को ऐसे लिखत उचित लागत पर प्रदान करने चाहिए, जिनकी उन्हें इन जोखिमों के प्रबंध के लिए जरूरत है।

इसी प्रकार, तीव्र विकास के लिए बुनियादी संरचना में अत्यधिक निवेश की जरूरत है और इसका अधिकांश भाग दीर्घकालिक ऋण के रूप में उपलब्ध कराना होगा। बैंक अब आदर्शतः दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं और यह घरेलू कॉरपोरेट ऋण बाजार विकसित करने की जरूरत को रेखांकित करता है। इसके लिए भी कार्य की सोची-समझी योजना की जरूरत है।

अंत में, सही मायने में समावेशी विकास के लिए बैंकिंग अब तक जहां पहुंची है, उससे आगे कई और लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी और मोबाइल बैंकिंग के रूप में प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों ने बैंकिंग प्रणाली की संभावित पहुंच को काफी बढ़ाया है। रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग एजेंटों की प्रणाली विकसित करने की अनुमति देने में पहले ही सराहनीय लचीलापन प्रदर्शित किया है। इसे बैंकिंग सेवाओं के और विस्तार के लिए प्रतिबद्ध बने रहना चाहिए ताकि बैंक अधिक से अधिक आम जनता की जिंदगी को छू सकें। हमारी बैंकिंग प्रणाली का हमारे कृषकों, लघु एवं मझोल उद्योगों और प्राथमिकतप्राप्त अन्य क्षेत्रों की ऋण जरूरतों पर से ध्यान कभी नहीं हटना चाहिए। वित्तीय समावेश के लाभ सुपात्र आम जनता तक पहुंचने से पहले हमें लंबा रास्ता तय करना है।

रिज़र्व बैंक ने अपने अस्तित्व के 75 वर्षों में अत्यधिक श्रेष्ठता से हमारे देश की सेवा की है। मैं इस प्रार्थना के साथ अपनी बात पूरी करता हूं कि सबसे अच्छी बातें अभी आनी बाकी हैं और इसके अगले 75 वर्ष हमारे महान देश के लिए अधिक उत्पादक और अधिक सृजनात्मक होंगे। मैं भारतीय रिज़र्व बैंक और इसके स्टाफ को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।